(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान किन-किन राज्यों में पोलीटैक्निक्स संस्थान खोले जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान गांधी नगर में एक पालिटेकनीक आरम्भ किया है ।

(ग) असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने वर्ष 1990-91 में पालिटेक्नीकों की स्थापना के प्रस्ताव किये थे ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फलैटों का आवंटन

2446. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फर्जी बैंक चालानों के आधार पर हजारों फ्लैटों का आवंटन किया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई छान-बीन की है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में ऐसे 6 मामले आए हैं जिनमें फर्जी बैंक चालानों के आधार पर कब्जा-पत्र जारी किए गए थे । दो अधिकारियों को निलम्बित किया गया है । आगे छानबीन के लिए मामला पुलिस उपायुक्त, क्राइम तथा रेलवे को भेजा गया है ।

Memorandum by All India Council of Mayors

2447. SHRI PRAMOD MAHAJAN. Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gov. eminent have received a memoran dum from the All India Council of Mayors; and

(b) if so, what are the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) and (b) The All India Council of Mayors have been submitting memorandums concerning various issues on urban development from time to time. The latest memorandum from the All India Council of Mayors was received on 27-11-1991. This memorandum contains suggestions with reference to the Constitution (72nd Amendment) and Constitution (73rd Amendment) Bills, 1991. The issues raised by them are summaried in the statement attached. (See below) Since the Constitution Bill relating to Urban Local Bodies (73rd Amendment) Bill has already been introduced in the Lok Sabha, these issues would have to form part of the debate in the Parliament when the Bill is taken up for consideration.